

Daily Current Affairs

Date : 18 February, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	भारत विस्तार' का राष्ट्रीय शुभारंभ जयपुर से
2.	इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 'राजस्थान AI पवेलियन'
3.	आय-व्ययक अनुमान 2026-27 के दौरान प्रमुख घोषणाएं
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम - 2026 2. CA विजय कुमार चौधरी : CA CXO-फॉर लार्ज कॉर्पोरेट-सर्विसेज सम्मान 3. डॉ. मुनिश भाटेजा 4. थार सांस्कृतिक सर्किट
5.	आपातकालीन लैंडिंग सुविधा
6.	ओल चिकी स्क्रिप्ट
7.	वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग
8.	चीर तीतर (Cheer Pheasant)
9.	कृषि में चक्रिय अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट से संपदा

--1:--



राजस्थान परिदृश्य



भारत विस्तार' का राष्ट्रीय शुभारंभ जयपुर से

चर्चा में क्यों?

- कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 17 फरवरी, 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री ने जयपुर में "भारत विस्तार योजना" के पहले चरण का शुभारंभ किया।

मुख्य बिन्दु:

- एग्री कोष (Agri Kosh) और रोडमैप : इस अवसर पर राज्य कृषि प्रबंध संस्थान (SIAM), दुर्गापुरा (जयपुर) से केन्द्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसान केंद्रित AI हैकाथॉन तथा एग्री कोष और AI स्ट्रेटेजी रोडमैप का भी अनावरण किया गया।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 'भारत विस्तार' AI आधारित एक बहुभाषी, AI-आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली है, जो देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि संबंधी समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान "155261" नंबर पर डायल करके अपनी समस्या बताएंगे और उन्हें तुरंत उसका समाधान मिलेगा।
- इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, रीयल-टाइम मंडी मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण एवं बीमा जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता व आवेदन मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ सरल एवं सुलभ रूप में प्राप्त होंगी।

- यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और जोखिम को न्यूनतम करना है।
- इस प्रणाली को एग्रीस्टेक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है।
- साथ ही, 'भारत विस्तार' विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों एवं राज्य स्तरीय डिजिटल प्रणालियों से जुड़कर किसानों को एक ही स्थान पर सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान बजट 2026-27 में कृषक कल्याण संबंधी प्रमुख घोषणाएं:

- **मिशन राज GIFT** : राज्य के विशिष्ट एग्रो-प्रोसेस्ड उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मिशन राज GIFT (जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स) की शुरुआत।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE)

- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओनियन एण्ड वेजिटेबल्स - अलवर।**
- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू - श्रीगंगानगर।**
- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो - बांसवाड़ा।**
- **नोट : जोधपुर, कोटा व उदयपुर में 'ऑर्गेनिक फूड मार्केट' की स्थापना की जाएगी।**

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 'राजस्थान AI पवेलियन'

चर्चा में क्यों?

- 16 से 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'AI इंपैक्ट समिट - 2026' में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान द्वारा 'राजस्थान AI पवेलियन' स्थापित किया गया।



The poster for the India AI Impact Summit 2026 features the DIT.C logo (Department of Information Technology & Communication, Rajasthan) and the Government of Rajasthan emblem. The central text reads 'India AI Impact Summit 2026' with the tagline 'Shaping Global AI from the Global South'. Below this, it states 'Global summit on AI for development (16-20 Feb, New Delhi)'. The poster also includes the motto 'सर्वजन हिताय | सर्वजन सुखाय' and 'WELFARE FOR ALL | HAPPINESS OF ALL'.

मुख्य बिन्दु:

- पवेलियन की थीम : 'पीपल, प्लेनेट एण्ड प्रोग्रेस'।
- संबंधित विभाग : सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
- 'राजस्थान AI पवेलियन' में 20 स्टॉल लगाई गई जहाँ विभिन्न विभागीय और सरकारी पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के 'आईस्टार्ट' पंजीकृत AI स्टार्टअप्स को शामिल किया गया।

Daily Current Affairs

Date : 18 February, 2026



- पवेलियन में 'राजकिसान' के माध्यम से AI आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, राजस्थान जन आधार प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा-संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा 'SMART' (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रणाली के जरिए रियल-टाइम योजना मॉनिटरिंग को प्रदर्शित किया गया।
- साथ ही, इस पवेलियन में राजनिवेश के साथ 'राज GPT' आधारित निवेश सुविधा प्रणाली को प्रस्तुत किया गया, जो निवेशकों को प्रोत्साहन, भूमि प्रक्रिया और अनुमोदन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- पवेलियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित राजस्थान की तीन प्रमुख नीतियों को भी प्रदर्शित किया गया। यथा - राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी - 2025 एवं राजस्थान AVGC-XR पॉलिसी - 2024

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस - 2026 : 06 जनवरी, 2026 को जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से।

राजस्थान AI-ML पॉलिसी - 2026

- **लॉन्च** : मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 06 जनवरी, 2026 को जयपुर में 'राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस - 2026' के दौरान।
- **पूरा नाम** : राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड मशीन लर्निंग (AI-ML) पॉलिसी - 2026
- **घोषणा** : राजस्थान बजट 2025-26 में।
- **अनुमोदन** : राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 30 दिसंबर, 2025 को।

--:5:--

Daily Current Affairs

Date : 18 February, 2026



- **उद्देश्य :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- **नोट :** नीति में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।



--:6:--

आय-व्ययक अनुमान 2026-27 के दौरान प्रमुख घोषणाएं

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आय-व्ययक अनुमान 2026-27 पर सदन में सामान्य चर्चा के दौरान बजट 2026-27 के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

मुख्य बिन्दु:

- नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर** : खारा राठौड़ान (रामसर), बाड़मेर और मदरामपुरा (सांगानेर), जयपुर।
- STRI (सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव) योजना** : बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउन्सलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए STRI (सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव) योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत लगभग एक लाख महिलाओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- मिनी सचिवालय** : लूणकरणसर (बीकानेर) में।
- IIIT, कोटा में नए कोर्स** : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) कोटा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा एनालिसिस और अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में नए कोर्स प्रारम्भ किये जाएंगे एवं इसे IT हब के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से DPR बनाई जाएगी।
- औद्योगिक विकास** : कोटा-बूंदी में निर्माणाधीन नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास RIICO द्वारा वृहद् औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
- रोबोटिक हैंड फॉर प्रोस्टेटिक सर्जरी फॉर यूरोलॉजी** : मेडिकल कॉलेज, कोटा में।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम - 2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन स्थल : 16-17 फ़रवरी, 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर।■ आयोजक : विद्या भारती, राजस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा संयुक्त रूप से।■ मुख्य विषय : "अंतर-संस्थागत विकास पर एक संवाद"।■ उद्देश्य : शिक्षण संस्थानों के नेतृत्व को सशक्त बनाना और आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा व नवाचार को बढ़ावा देना।
2.	<p>CA विजय कुमार चौधरी : CA CXO-फॉर लार्ज कॉर्पोरेट-सर्विसेज सम्मान</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, NBCC (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक CA विजय कुमार चौधरी को प्रतिष्ठित 'सीए सीएक्सओ - फॉर लार्ज कॉर्पोरेट - सर्विसेज' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।■ यह पुरस्कार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा 19वें ICAI पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जो 'वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग' (WOFA) - 2026 के अवसर पर आयोजित हुआ था।

3.	<p>डॉ. मुनिश भाटेजा</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, मस्कट (ओमान) में आयोजित 'आयरनमैन 70.3 मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप' में राजस्थान के डॉ. मुनिश भाटेजा ने 1.9 किमी तैराकी, 90 किमी साइक्लिंग और 21.1 किमी दौड़ की ट्रायथलॉन को पूरा किया।
4.	<p>थार सांस्कृतिक सर्किट</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2026-27 में एक महत्वाकांक्षी पर्यटन परियोजना 'थार सांस्कृतिक सर्किट' की घोषणा की गई।शामिल जिले : जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर।इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध मरुस्थलीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को बढ़ावा देना और उन्हें एक सूत्र में पिरोना है।



राष्ट्रीय परिदृश्य

आपातकालीन लैंडिंग सुविधा

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मोरान बाईपास पर 4.2 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की पहली सुविधा है।

मुख्य बिन्दु:

- इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक मजबूत राजमार्ग खंड है जिसे भारतीय वायु सेना के लिए वैकल्पिक रनवे के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- शीत युद्ध के दौरान ईएलएफ (इलेक्ट्रो-लाइफ लैंडिंग सिस्टम) की अवधारणा सामने आई, जब देशों ने स्थायी हवाई अड्डों की असुरक्षा को कम करने के लिए राजमार्ग रनवे विकसित किए। फिनलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देश अभी भी इस तरह के दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित, मोरान ईएलएफ संघर्ष की स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है और दूरस्थ क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करता है।
 - o यह 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन तक के परिवहन विमानों को संभाल सकता है।
- लगभग 15 ऐसी सुविधाएं अब तक चालू हो चुकी हैं, और यह रणनीतिक नेटवर्क राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे और अब पूर्वोत्तर की रणनीतिक सीमाओं तक फैला हुआ है।



ओल चिकी स्क्रिप्ट



चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया और संथाल विरासत के संरक्षण में इसके महत्त्व पर जोर दिया।



मुख्य बिन्दु:

- संथाली भाषा के लिए एक समर्पित लेखन प्रणाली प्रदान करने के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में ओल चिकी का विकास किया गया था।
- इसमें संथाली ध्वनियों को सटीकता से पकड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए 30 अक्षर शामिल हैं, जिससे इसकी शब्दावली और व्याकरण का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण संभव हो पाता है।
- संथाली, जो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार का एक सदस्य है, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में बोली जाती है।
 - o इसे 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

आर्थिक घटनाक्रम

वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार के लिए अमेरिका की मांगों से सहमति जताते हुए कहा कि यह प्रणाली लचीली तो है लेकिन मजबूत नहीं है।

मुख्य बिन्दु:

वैश्विक व्यापार प्रणाली और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाला एकमात्र वैश्विक निकाय है।
- उद्देश्य:** सदस्य देशों द्वारा बातचीत और अनुमोदित समझौतों के माध्यम से सुचारू, पूर्वानुमानित और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है।
- यह वैश्विक व्यापार नियमों का प्रबंधन करता है, समझौतों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, व्यापार विवादों का समाधान करता है और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता है।
- इसके निर्णय सदस्य सरकारों द्वारा जिनेवा में मंत्रियों या प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं।

उभरते मुद्दे

- **संरक्षणवाद में वृद्धि:** शुल्क और व्यापार बाधाओं के बढ़ते उपयोग से मुक्त व्यापार के मानदंड कमजोर हो रहे हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजारों को बाधित कर रही है।
- **कृषि संबंधी विवाद:** विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी व्यापार को विकृत करती है, जिससे विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ता है।
- **विवाद निपटान संकट:** विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय है, जिससे नियमों का प्रवर्तन कमजोर हो गया है।
- **डिजिटल और जलवायु संबंधी मुद्दे:** ई-कॉमर्स, डेटा प्रवाह और कार्बन टैक्स पर वैश्विक सहमति की कमी से नए व्यापारिक तनाव पैदा हो रहे हैं।

सुझाव

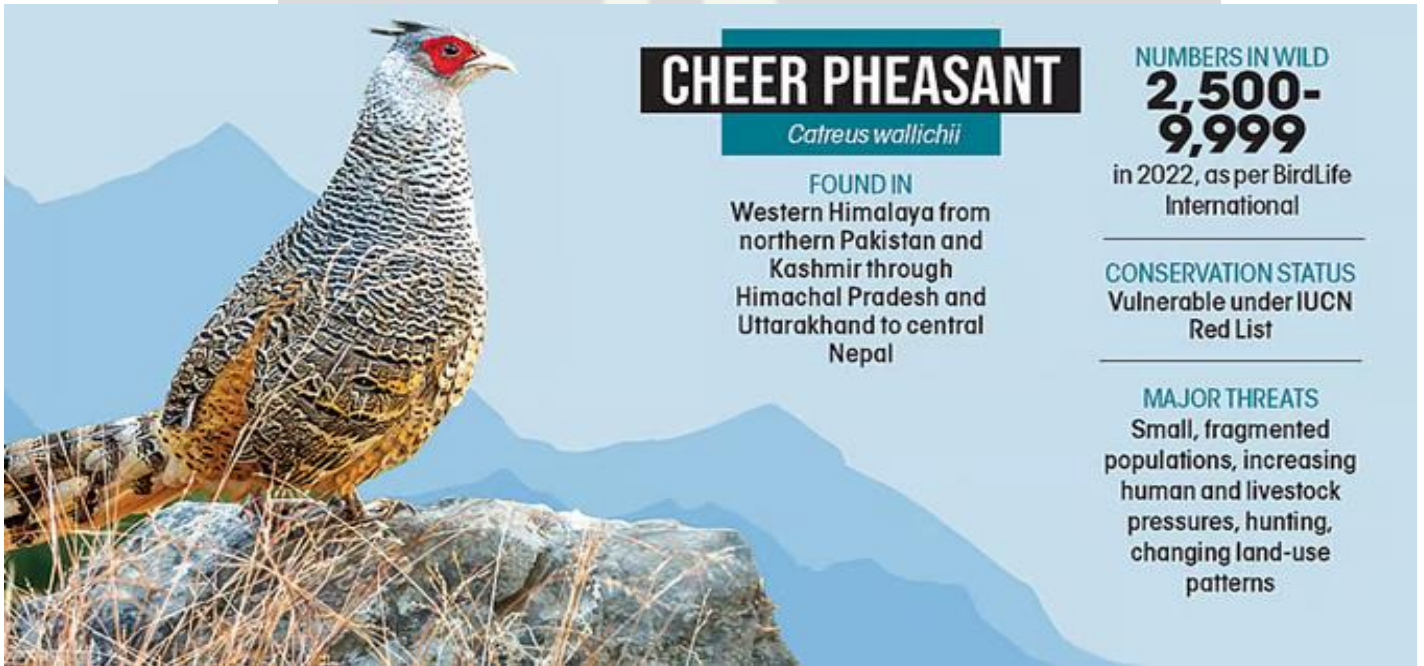
- विवाद निपटान को बहाल करें और डिजिटल व्यापार, सेवाओं और स्थिरता के लिए नियमों को अद्यतन करें।
- विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करें, विशेषकर कृषि और जलवायु व्यापार के मुद्दों पर।
- अत्यधिक निर्भरता को कम करने और स्थिरता में सुधार लाने के लिए स्रोतों में विविधता लाएं।
- व्यापार नीतियों को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दें।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

चीर तीतर (Cheer Pheasant)

चर्चा में क्यों?

- चीर तीतर की संख्या में गिरावट के प्रमुख कारण अब भी शिकार और पर्यावास का क्षरण हैं।



मुख्य बिन्दु:

- पर्यावास:** ये मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय के मध्य-पर्वतीय घास के मैदानों में प्राप्त होते हैं। ये पक्षी पाकिस्तान, भारत और नेपाल में देखे जा सकते हैं।
- संरक्षण स्थिति:**
 - IUCN:** वल्नरेबल
 - CITES:** परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध

कृषि में चक्रिय अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट से संपदा

चर्चा में क्यों?

- भारत में कृषि अपशिष्ट का उत्पादन हर साल बढ़ता जा रहा है, जो एक गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है।
- भारत में हर वर्ष 350 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें फसल अवशेष, भूसी, पुआल और खाद्य प्रसंस्करण से प्राप्त उप-उत्पाद शामिल हैं।
- अगर इन अपशिष्टों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता, तो यह वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बन सकता है। हालांकि, इन कृषि अपशिष्टों को ऊर्जा, जैविक खाद और जलवायु अनुकूल उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया चक्रिय अर्थव्यवस्था के तहत सुगम बनाई जा रही है।



मुख्य बिन्दु:

चक्रिय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण:

- **अपशिष्ट से संपदा दृष्टिकोण:** चक्रिय अर्थव्यवस्था में, "अपशिष्ट से संपदा" दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जिसमें कृषि अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में पुनः परिभाषित किया जाता है।
- **संरचनात्मक बदलाव:** यह अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग के पारंपरिक तरीकों में एक संरचनात्मक बदलाव लाती है, जिसमें कच्चे माल, जल और ऊर्जा का कम से कम उपयोग किया जाता है।
- **चक्रिय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत:** चक्रिय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों में पुनर्प्राप्ति, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और मरम्मत पर जोर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण संसाधन दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन को सर्वोत्तम तरीके से लागू करता है, जिससे पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता है।

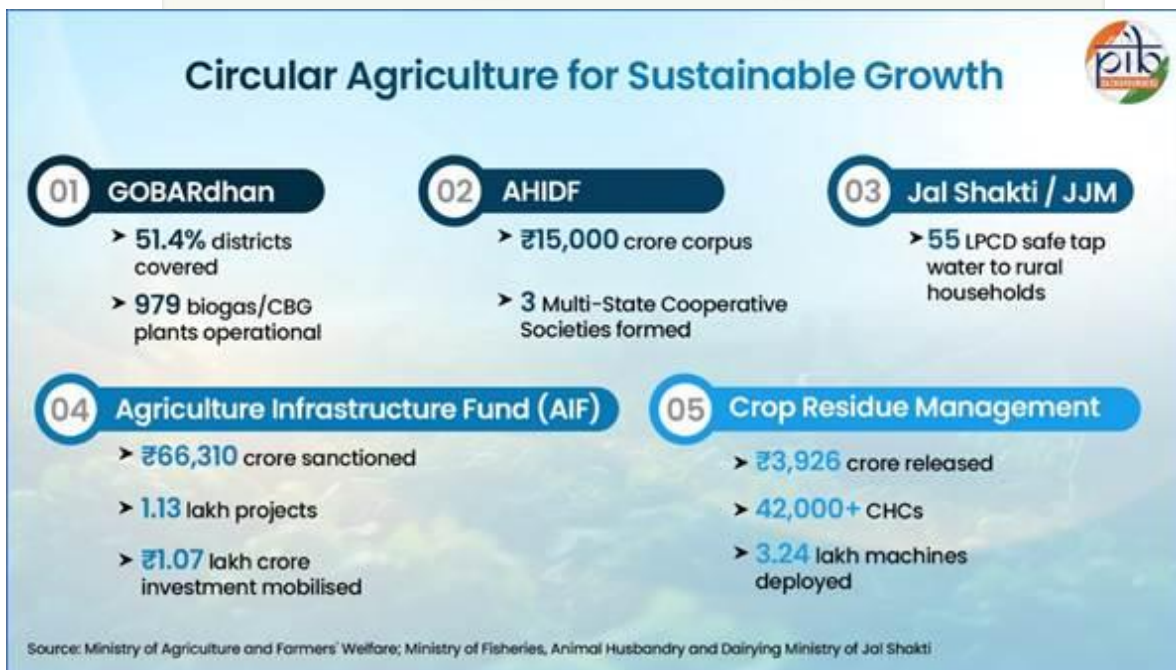


--:16:--

चक्रिय कृषि की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

भारत सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अपशिष्ट को संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं:

- गोबरधन योजना:** इस योजना के तहत गोबर, फसल अवशेष और खाद्य अपशिष्ट को जैविक खाद और बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। 14 जनवरी 2026 तक, भारत के 51.4% जिलों में 979 बायोगैस संयंत्र कार्यरत हैं।
- फसल अवशेष प्रबंधन (CRM):** इस पहल का उद्देश्य खुले में फसल अवशेष जलाने को कम करना है, और इन अवशेषों का उपयोग कम्पोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन और जैव-ऊर्जा के रूप में किया जाता है।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF):** यह कोष जैविक खेती और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि में चक्रियता को बढ़ावा मिलता है।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF):** यह कोष मांस, दुग्ध प्रसंस्करण, पशु आहार उत्पादन और 'अपशिष्ट से संपदा' प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे पशुपालन क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और दक्षता में वृद्धि होती है।



--:17::--

Daily Current Affairs

Date : 18 February, 2026



चक्रिय कृषि के लाभ:

- **सतत विकास:** चक्रिय कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करती है।
- **सामाजिक और आर्थिक समावेशन:** यह ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में योगदान देती है, खासकर फसल अवशेष और बायोमास के उपयोग से।
- **पर्यावरण संरक्षण:** जैविक खाद और बायोगैस के उत्पादन से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जिससे पर्यावरण पर दबाव कम होता है।

निष्कर्ष:

- चक्रिय कृषि, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को समर्थन देते हुए भारत को एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थिर और आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बना रही है।

-:18:-